

कनिमोझी करुणानिधि

बनाम

ए. संताना कुमार एवं अन्य

(2023 की दीवानी अपील सं. 3411)

04 मई, 2023

[अजय रस्तोगी और बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्तिगण]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 83(1)(ए) - की अवहेलना - के परिणाम -
अभिनिर्धारित: धारा 83(1)(ए) यह अनिवार्य करती है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है - यदि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो इसे केवल उस आधार पर खारिज किया जा सकता है, क्योंकि यह वाद दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (ए) के अंतर्गत आएगा - दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 7, नियम 11(ए).

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 100(1)(डी)(iv), 83(i)(ए) - उत्तरदाता संख्या 1 ने यह घोषणा मांगते हुए चुनाव याचिका दायर की कि लोकसभा चुनाव में संख्या 36, थूथुकुडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपीलकर्ता -निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य था और अपास्त किए जाने योग्य था - यह आधार दिया गया था कि अपीलकर्ता ने प्रपत्र संख्या 26 में शपथ पत्र में अपने पति (अपीलकर्ता के अनुसार एक विदेशी नागरिक) के आयकर भुगतान के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की थी - अपीलकर्ता ने चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की, आवेदन खारिज कर दिए गए - अभिनिर्धारित: अपीलकर्ता ने अपने स्थायी खाता संख्या

(पैन) और आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति आदि और जहां लागू हो, अपने पति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करके प्रपत्र संख्या 26 के सभी कॉलम भरे थे - यदि उत्तरदाता के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपने पति के पैन को छिपाया था और विदेशी देश में अपने पति द्वारा आयकर का भुगतान न करने के बारे में भी छिपाया था, तो उत्तरदाता की ओर से चुनाव याचिका में यह बताना अनिवार्य था कि भारत में अपीलकर्ता के पति का पैन क्या था जिसे उसने छिपाया था और उक्त प्रपत्र संख्या 26 में उसके पति के बारे में प्रस्तुत अन्य विवरण कैसे अधूरे या झूठे थे - बिना किसी आधार के केवल कोरे और अस्पष्ट आरोप चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य बताने की आवश्यकता के पर्याप्त अनुपालन नहीं होंगे - याचिका में धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत वाद हेतु गठित करने वाले कोई भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं - चुनाव याचिका को आदेश VII, नियम 11(ए), दीवानी प्रक्रिया संहिता पठित धारा 83(i)(ए) के तहत खारिज किया जाता है - उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है - चुनाव संचालन नियम 1961 - नियम 4, 4 ए - भारत का संविधान - अनुच्छेद 324 - दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 - आदेश 7, नियम 11(ए).

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - चुनने का अधिकार, चुने जाने का अधिकार और चुनाव को विवादित करने का अधिकार - प्रकृति - अभिनिर्धारित: चुनने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून अधिकार - यह पूर्णतः एक वैधानिक अधिकार है - इसी प्रकार, चुने जाने का अधिकार और चुनाव को विवादित करने का अधिकार भी वैधानिक सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार हैं - एक चुनाव याचिका सामान्य कानून पर कोई कार्रवाई नहीं है, और न ही समता में - यह एक विशेष क्षेत्राधिकार है जिसका प्रयोग इसे बनाने वाले कानून के अनुसार किया जाना चाहिए - चुनाव याचिका एक गंभीर मामला है, इसे हल्के में या

काल्पनिक तरीके से नहीं लिया जा सकता है और न ही यह किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इसका उपयोग तंग करने वाले उद्देश्य के लिए करता है - भारत का संविधान - भाग-XV.

शब्द और वाक्यांश - "भौतिक तथ्य" - क्या गठित करता है - चर्चा की गई - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - धारा 83(1)(ए).

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 83(1)(ए) यह अनिवार्य करती है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है। यदि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो इसे केवल उस आधार पर खारिज किया जा सकता है, क्योंकि यह वाद संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (ए) के अंतर्गत आएगा। भौतिक तथ्य ऐसे तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए आधार प्रदान करें और वाद हेतु कारण का गठन करें, अर्थात् प्रत्येक तथ्य जिसे साबित करना वादी/याचिकाकर्ता के लिए आवश्यक होगा, यदि न्यायालय के निर्णय के लिए उसके अधिकार का समर्थन करने के लिए उसका खंडन किया जाता है। एक भी भौतिक तथ्य का लोप अपूर्ण वाद हेतु कारण की ओर ले जाएगा और अभियोग का कथन खराब हो जाएगा। भौतिक तथ्यों का अर्थ है तथ्यों का पूरा समूह जो पूर्ण वाद हेतु का गठन करेगा। भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक बयान और साथ ही यदि आवश्यक हो तो नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रकथन शामिल होगा। आरपी अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत चुनाव को शून्य घोषित करवाने के लिए, चुनाव याचिकाकर्ता को यह दावा करना होगा कि संविधान या अधिनियम के प्रावधानों या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या

आदेश की अवहेलना के कारण, चुनाव का परिणाम, जहां तक इसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। चुनाव याचिका एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में या काल्पनिक तरीके से नहीं लिया जा सकता है और न ही यह किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इसका उपयोग तंग करने वाले उद्देश्य के लिए करता है। एक चुनाव याचिका को अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाने वाले एक भी भौतिक तथ्य के लोप पर, या वाद हेतु स्थापित करने के लिए जिन भौतिक तथ्यों पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है उनका संक्षिप्त विवरण शामिल करने में लोप पर, आरपी अधिनियम की धारा 83 द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ पठित दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII के नियम 11 के खंड (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संक्षेप में खारिज किया जा सकता है। [कंडिका 28] [825-बी-एच; 826-ए]

1.2 चुनाव याचिकाकर्ता यानी उत्तरदाता ने यह भौतिक तथ्य बताए बिना बहुत ही कोरे और अस्पष्ट आरोप लगाए हैं कि भारत के संविधान या आरपी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान की अवहेलना कैसे हुई थी। यदि चुनाव याचिका में किए गए दावों को अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्रपत्र संख्या 26 में दी गई जानकारी के साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट रूप से उभरता है कि अपीलकर्ता के पति के पैन नंबर के बारे में मांगी गई जानकारी के सामने, यह कहा गया है कि "कोई पैन नंबर नहीं", "पति के. अरविंदन विदेशी नागरिकता"। "वित्तीय वर्ष जिसके लिए पिछला आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है" के संबंध में मांगी गई जानकारी के सामने, अपीलकर्ता द्वारा अपने पति के बारे में दी गई जानकारी "लागू नहीं" है। अपीलकर्ता ने अपने स्थायी खाता संख्या और आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति आदि और जहां लागू हो, अपने पति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करके प्रपत्र संख्या 26 के सभी कॉलम भरे हैं। यदि उत्तरदाता-चुनाव याचिकाकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार ने

अपने पति के स्थायी खाता संख्या और विदेश में अपने पति द्वारा आयकर का भुगतान न करने के बारे में भी छिपाया था, तो चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव याचिका में यह बताना अनिवार्य था कि भारत में निर्वाचित उम्मीदवार के पति का स्थायी खाता संख्या क्या था जिसे उसने छिपाया था और उक्त प्रपत्र संख्या 26 में उसके पति के बारे में प्रस्तुत अन्य विवरण कैसे अधूरे या झूठे थे। बिना किसी आधार के केवल कोरे और अस्पष्ट आरोप चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य बताने की आवश्यकता के पर्याप्त अनुपालन नहीं होंगे। [कंडिका 30, 31][826-जी-एच; 827-ए-डी]

1.3 यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उक्त नियमों के नियम 4ए के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 33 के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रपत्र 26 में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्वाचन अधिकारी को किसी भी नामांकन पर की गई आपत्तियों पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, धारा 36(2) में उल्लिखित आधारों पर किसी भी नामांकन को खारिज करने का अधिकार है, जिसमें यह आधार भी शामिल है कि अधिनियम की धारा 33 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता हुई है। हालांकि, नामांकन पत्र और अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 26 में शपथपत्र की जांच के समय, न तो कोई आपत्ति उठाई गई थी, और न ही निर्वाचन अधिकारी ने धारा 33 या नियमों के नियम 4ए की कोई त्रुटि या अवहेलना पाई थी। यह मानते हुए कि चुनाव याचिकाकर्ता के पास अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भरे गए प्रपत्र संख्या 26 को देखने का अवसर नहीं था, जब उसने उसे निर्वाचन अधिकारी को सौंपा था, और यह मानते हुए कि निर्वाचन अधिकारी ने अपीलकर्ता के नामांकन पत्र की ठीक से जांच नहीं की थी, और यह मानते हुए कि चुनाव याचिकाकर्ता को उक्त 34 अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत चुनाव याचिका दायर

करके उस पर सवाल उठाने का अधिकार था, तब भी याचिका में धारा 100(1)(डी)(iv) आरपी अधिनियम के तहत वाद हेतु का गठन करने वाले कोई भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं। उक्त अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत चुनाव याचिका दायर करने के लिए वाद हेतु का गठन करने वाले भौतिक तथ्यों के अभाव में, चुनाव याचिका को आदेश VII नियम 11(ए) दीवानी प्रक्रिया संहिता पठित आरपी अधिनियम की धारा 13(1)(ए) के तहत खारिज किया जाना आवश्यक है। आरपी अधिनियम की धारा 83(1)(ए) यह अनिवार्य करती है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है, और जो तथ्य वाद हेतु का गठन करते हैं। ऐसे तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक बयान और साथ ही नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रकथन शामिल होगा। एक भी तथ्य का लोप अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाएगा। जहां तक वर्तमान याचिका का संबंध है, ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि संविधान या आरपी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेश के प्रावधानों की अवहेलना कैसे हुई और ऐसी अवहेलना ने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से कैसे प्रभावित किया, जिससे चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए आरपी अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत आधार आकर्षित हो। ऐसे महत्वपूर्ण और बुनियादी तथ्यों को बताने में लोप ने याचिका को आदेश VII, नियम 11(ए) दीवानी प्रक्रिया संहिता पठित आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 83(i)(ए) के तहत खारिज किए जाने योग्य बना दिया है। उत्तरदाता-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका खारिज की जाती है। [कंडिका 33, 34][827-एफ-एच; 828-ए-एफ]

एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र एवं अन्य,
1952 (1) एस.सी.सी. 94; *जगन नाथ बनाम जसवंत सिंह एवं अन्य, ए.आई.आर.*

1954 एस.सी. 210 : [1954] एस.सी.आर. 892; भीकाजी केशव जोशी एवं अन्य बनाम बृजलाल नंदलाल बियानी एवं अन्य, ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 610 : [1955] एस.सी.आर. 428; मुरारका राधेश्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौर एवं अन्य, ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 1545 : [1964] एस.सी.आर. 573 – अनुसरण किया गया।

राम सुख बनाम दिनेश अग्रवाल, 2009 (10) एस.सी.सी. 541 : [2009] 14 एस.सी.आर. 836; हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी, 2001 (8) एस.सी.सी. 233 : [2001] 3 एस.सी.आर. (पूरक) 38; सामंत एन. बालकृष्ण एवं अन्य बनाम जॉर्ज फर्नांडीज एवं अन्य, 1969 (3) एस.सी.सी. 238 : [1969] 3 एस.सी.आर. 603; भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य, 2002 (5) एस.सी.सी. 294 : [2002] 3 एस.सी.आर. 696; महादेवराव सुकाजी शिवनकर बनाम रामरतन बापू एवं अन्य, 2004 (7) एस.सी.सी. 181 : [2004] 3 एस.सी.आर. (पूरक) 553; अनिल वासुदेव सालगांवकर बनाम नरेश कुशली शिगांवकर, 2009 (9) एस.सी.सी. 310 : [2009] 14 एस.सी.आर. 10 – अवलंबित।

नजीर संदर्भ:

[2009] 14 एस.सी.आर. 836	अवलंबित	कंडिका 7 (ii)
[2001] 3 एस.सी.आर. (पूरक) 38	अवलंबित	कंडिका 7 (ii)

[1969] 3 एस.सी.आर. 603	अवलंबित	कंडिका 7 (iii)
[2002] 3 एस.सी.आर. 696	अवलंबित	कंडिका 8 (i)
[1954] एस.सी.आर. 892	अनुसरण किया गया	कंडिका 18
[1955] एस.सी.आर. 428	अनुसरण किया गया	कंडिका 18
[1964] एस.सी.आर. 573	अनुसरण किया गया	कंडिका 18
[2002] 3 एस.सी.आर. 696	अवलंबित	कंडिका 20
[2004] 3 एस.सी.आर. (पूरक) 553	अवलंबित	कंडिका 25
[2009] 14 एस.सी.आर. 10	अवलंबित	कंडिका 26

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2023 की दीवानी अपील सं. 3411.

मद्रास उच्च न्यायालय के मूल आवेदन संख्या 929 और 930/2019 में दिनांक 19.11.2019 के निर्णय और आदेश से।

साथ में

2023 की दीवानी अपील सं. 3412.

पी. विल्सन, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. जोसेफ अरस्तू एस, रिचर्डसन विल्सन, अपूर्व मल्होत्रा, सुश्री सपना आई पिल्लई, सुश्री ऐश्वर्या मिश्रा, सुश्री प्रिया अरस्तू अपीलकर्ता के लिए अधिवक्तागण।

एस. मुकेश, एन. आई. रामचंद्रन, एल. आर. वेंकटेशन, अनूप प्रकाश अवस्थी, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अपर्णा सिंह, सुश्री साक्षी उपाध्याय, अधिवक्तागण उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया:

बेला एम. त्रिवेदी न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. दोनों अपीलों में अपीलकर्ता (जिसे इसके बाद निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में संदर्भित किया जाएगा) ने चुनाव याचिका संख्या 3/2019 में अपीलकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन संख्या 929/2019 और 930/2019 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.11.2019 के आक्षेपित सामान्य आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया है।

तथ्यात्मक ढांचा:

3. वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाला तथ्यात्मक ढांचा यह है कि 19.03.2019 को, 18.04.2019 को निर्धारित 17 वीं लोकसभा चुनावों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में नामांकन आमंत्रित किए गए थे। अपीलकर्ता ने संख्या 36-थूथुकुडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया, साथ में चुनाव संचालन नियम 1961 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 4 ए के अनुसार प्रपत्र संख्या 26 में शपथपत्र भी दिया। नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारी द्वारा 27.03.2019 को की गई थी। चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18.04.2019 को आयोजित किए गए थे, और अपीलकर्ता को 23.05.2019 को 3,47,209 मतों के अंतर से उक्त संख्या 36 थूथुकुडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किया गया था।

4. चुनाव याचिकाकर्ता/उत्तरदाता संख्या 1 जो एक मतदाता होने का दावा करता है, ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसके बाद आरपी अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 80, 80 ए, 100(1)(डी)(iv) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका संख्या 3/2019 दायर की है, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की दिनांक 19.03.2019 की अधिसूचना के अनुसरण में आयोजित लोकसभा चुनाव में संख्या 36, थूथुकुडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार, यानी अपीलकर्ता का चुनाव शून्य था और अपास्त किए जाने योग्य था, इस आधार पर कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उसके पति के आयकर भुगतान के संबंध में मांगी गई जानकारी उसके द्वारा नामांकन पत्रों के साथ जमा किए गए शपथपत्र - प्रपत्र संख्या 26 में प्रदान नहीं की गई थी, और इस प्रकार जानबूझकर छिपाया गया था और मतदाताओं को इसका खुलासा नहीं किया गया था।

5. चुनाव याचिका की कंडिका 5 से 9 में लगाए गए सटीक आरोप इस प्रकार हैं:

"5. याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता है कि निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 4 के तहत उत्तरदाता संख्या 2, जो कि निर्वाचित उम्मीदवार है, द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र के अवलोकन पर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इसे जनता के लिए प्रसारित करने के बाद, यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि वह तमिल भाषा में "थुनिवर" अर्थात् अरविंदन, सिंगापुर के नागरिक, के रूप में उल्लिखित अपने पति के आयकर के भुगतान का विवरण देने में विफल रही है, उस कॉलम में जहां पैन नंबर, आयकर रिटर्न दाखिल करने का पिछला वित्तीय वर्ष और पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न में दिखाई गई कुल आय, प्रत्येक वर्ष के लिए रुपये में, प्रदान करने की आवश्यकता होती है, शपथपत्र प्रपत्र 26 में, भाग ए, संख्या 4 क्रम सं. 2 के तहत, तमिल भाषा में "पौरुथेथु" का उल्लेख करके, जो जानकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी के पालन में निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जानी है और निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भारत के संविधान के प्रावधानों की अवहेलना में इसे छिपाने से, चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।

6. याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता है कि शपथपत्र प्रपत्र 26 के भाग-बी के क्रम सं. 3 में उत्तरदाता संख्या 2 ने निर्वाचन क्षेत्र संख्या, नाम और राज्य के संबंध में जानकारी संख्या 36, थूथुकुडी, तमिलनाडु के रूप में प्रदान की थी, लेकिन जबकि भाग ए संख्या 2 में, उसने उल्लेख किया कि उसका चुनावी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19 चेपक, तमिलनाडु है, जो नामांकन पत्र के अनुचित प्रस्तुतीकरण को उजागर करता है।

7. याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता है कि उत्तरदाता संख्या 2, जो निर्वाचित उम्मीदवार है, के असंवैधानिक कृत्य से व्यथित होकर, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता आयकर रिटर्न में प्रकट निर्वाचित उम्मीदवार के पति की आय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ हैं, फलस्वरूप चूंकि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित है, वह इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना कर रहा है कि संख्या 36, थूथुकुडी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार, यहाँ उत्तरदाता संख्या 2, के चुनाव को शून्य घोषित किया जाए और उसे अपास्त किया जाए।

8. याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि नामांकन पत्र, शपथपत्र प्रपत्र 26 उसके पति (थुनिवर) अर्थात श्री अरविंदन, सिंगापुर के नागरिक, के आयकर की राशि के भुगतान के विवरण के बिना है, हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जनता को जानकारी प्रदान करने के मद्देनजर भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयकर की राशि के भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा, यहां यह बताना प्रासंगिक है कि विदेशी देशों से आय सिंगापुर आयकर अधिनियम के तहत आयकर के अधीन है और प्रत्येक आयकर दाता को प्राधिकरण द्वारा आयकर संदर्भ संख्या प्रदान की जाती है।

9. याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता है कि निर्वाचित उम्मीदवार, यहाँ उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपने पति के आयकर भुगतान के संबंध में (थुनिवर) जानकारी छिपाना, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को सिंगापुर में आयकर प्राधिकरण को आयकर भुगतान की

पूरी जानकारी प्राप्त करने से वंचित करता है और नियमों का पालन न करते हुए झूठा शपथपत्र दायर करने की ओर ले जाता है।"

6. उक्त चुनाव याचिका में, अपीलकर्ता/निर्वाचित उम्मीदवार ने मूल आवेदन संख्या 929/2019 दायर किया था जिसमें चुनाव याचिका की कंडिका 5 से 17 को हटाने की प्रार्थना की गई थी और मूल आवेदन संख्या 930/2019 दायर किया था जिसमें चुनाव याचिका को प्रारंभ में ही खारिज करने की प्रार्थना की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आधार था कि चुनाव याचिका में निहित कथन और आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट थे और भौतिक तथ्यों से रहित थे, और इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 81, 83, 86 और 100 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते थे। यह भी कहा गया था कि चुनाव याचिका की कंडिका संख्या 5 से 17 भौतिक तथ्यों से रहित थीं और किसी भी वाद हेतु का खुलासा नहीं करती थीं। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता/निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा दायर दोनों मूल आवेदनों को खारिज कर दिया।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दलीलें:

7. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. विल्सन ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 83(1)(ए) सभी चुनाव याचिकाओं के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि उनमें उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण हो जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है, हालांकि वर्तमान मामले में उत्तरदाता-चुनाव

याचिकाकर्ता भौतिक तथ्यों का अभिवचन करने में विफल रहा है और इसलिए चुनाव याचिका आरम्भ में ही खारिज किए जाने योग्य है।

- (ii) *राम सुख बनाम दिनेश अग्रवाल*¹ के मामले में और *हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी*² के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलंबन करते हुए , उन्होंने प्रस्तुत किया कि भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक बयान और साथ ही यदि आवश्यक हो तो नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रकथन शामिल होगा, और इसके अभाव में, चुनाव याचिका केवल उस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है।
- (iii) *सामंत एन. बालकृष्ण एवं अन्य बनाम जॉर्ज फर्नांडीज एवं अन्य*³ पर अवलंबन करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक भी भौतिक तथ्य का अभिवचन करने में विफलता अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाती है और दावे का बयान गलत हो जाता है।
- (iv) तत्काल मामले में, हालांकि उत्तरदाता-चुनाव याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अपीलकर्ता ने प्रपत्र संख्या 26 शपथपत्र में तथ्यों को छिपाया है, वह यह बताने में विफल रहा है कि कौन से तथ्य छिपाए गए थे, और कैसे संविधान या अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों की अवहेलना हुई थी, जिसने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया था।

1 2009 (10) एससीसी 541

2 2001 (8) एससीसी 233

3 1969 (3) एससीसी 238

- (v) उत्तरदाता द्वारा दायर पूरी चुनाव याचिका भौतिक तथ्यों, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) में निहित आधार के समर्थन में भौतिक तथ्यों को बताए बिना अस्पष्ट और कोरे अनुमानों, धारणाओं और अटकलों पर आधारित है।
- (vi) अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि उम्मीदवारों को अपनी आयकर की स्थिति, संपत्ति और देनदारियों के साथ-साथ अपने जीवनसाथी की संपत्ति और देनदारियों का खुलासा करना आवश्यक है, यदि तथ्य की स्थिति में इस संबंध में कॉलम लागू नहीं होते हैं, तो यह तथ्यों को छिपाना नहीं माना जा सकता है।

8. उत्तरदाता संख्या 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश एस. ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

- (i) *अपीलकर्ता ने भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं एक अन्य* में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन किया है, जिसमें न्यायालय ने चुनाव आयोग को नागरिकता की स्थिति में अंतर किए बिना, उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्राप्त करने का निर्देश दिया था।

- (ii) अपीलकर्ता ने अपने पति के आयकर बकाए के संबंध में प्रश्न के उत्तर में "नहीं" का उल्लेख किया था। अपीलकर्ता विदेश में अपने पति के आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति का खुलासा करने में विफल रही थी, जैसा कि प्रपत्र संख्या 26 में खुलासा करना आवश्यक है। अपीलकर्ता ने उक्त प्रपत्र में केवल यह कहा था कि उसका पति एक विदेशी नागरिक है, बिना आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति और सिंगापुर में प्रदान किए गए आयकर संदर्भ संख्या का खुलासा किए।
- (iii) अपीलकर्ता विदेश में अपने पति द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति का विवरण देने के लिए बाध्य थी और इसका खुलासा न करना तथ्यों को छिपाने और उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों की अवहेलना के बराबर था।
- (iv) अपने परिवार की वित्तीय स्थिति का खुलासा न करके, अपीलकर्ता ने मतदाताओं को वोट डालने के बारे में निर्णय लेने के अवसर से वंचित कर दिया था।
- (v) पारदर्शिता की कमी और प्रपत्र संख्या 26 में तथ्यों का खुलासा न करने से चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था।

भारत का संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधान:

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए परस्पर विरोधी तर्कों को समझने के लिए, भारत के संविधान और साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निहित कुछ प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना लाभकारी होगा।

10. भारत का संविधान का भाग-XV चुनावों से संबंधित है। संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के लिए सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी चुनावों के संचालन का और संविधान के तहत होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत का संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है। अनुच्छेद 325 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य निर्वाचक नामावली होगी और कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर ऐसी नामावली में शामिल किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अनुच्छेद 327 संसद को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदनों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 328 राज्य के विधान-मंडल को, यदि संसद ने ऐसा कानून नहीं बनाया है, तो राज्य के विधान-मंडल के सदनों के चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जित करता है और विशेष रूप से खंड (बी) यह प्रावधान करता है कि संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनाव को किसी ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे तरीके से प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका

के अलावा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा जैसा कि उपयुक्त विधान-मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया जा सकता है।

11. जहां तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का संबंध है, इसका उद्देश्य जैसा कि इसके संक्षिप्त नाम में परिलक्षित होता है, संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के चुनावों के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए अर्हताओं और निरर्हताओं, ऐसे चुनावों में या उनके संबंध में भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों और ऐसे चुनावों से उत्पन्न होने वाले या उनके संबंध में संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए प्रावधान करना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का भाग-VI चुनावों के संबंध में विवादों से संबंधित है, और उसका अध्याय II उच्च न्यायालय में चुनाव याचिकाओं के प्रस्तुतीकरण से संबंधित है। इसकी धारा 80 में कहा गया है कि भाग-VI के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत चुनाव याचिका के अलावा किसी भी चुनाव को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

12. धारा 80ए उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाओं पर विचारण (try) करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करती है। धारा 81 याचिकाओं के प्रस्तुतीकरण से संबंधित है जो इस प्रकार है:

"धारा 81. याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण- (1) किसी भी चुनाव को प्रश्नगत करने वाली चुनाव याचिका धारा 100 की [उप-धारा (1)] और धारा 101 में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार या किसी भी निर्वाचक द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है [निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, लेकिन उससे पहले नहीं, या यदि चुनाव में एक से अधिक

निर्वाचित उम्मीदवार हैं और उनके चुनाव की तारीखें अलग-अलग हैं, तो उन दो तारीखों में से बाद वाली तारीख]।

स्पष्टीकरण। —इस उप-धारा में, "निर्वाचक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार था जिससे चुनाव याचिका संबंधित है, चाहे उसने ऐसे चुनाव में मतदान किया हो या नहीं।

(2) [***]

[(3) प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ उसकी उतनी प्रतियां होंगी जितने याचिका में उल्लिखित उत्तरदाता हैं और ऐसी प्रत्येक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्वयं के हस्ताक्षर के तहत याचिका की सच्ची प्रति होने के लिए अनुप्रमाणित की जाएगी।]

13. धारा 82 यह अनिवार्य करती है कि चुनाव याचिका के पक्षकार कौन होंगे। धारा 83 याचिका की अंतर्वस्तु से संबंधित है, जो इस प्रकार है:-

83. याचिका की अंतर्वस्तु- (1) एक चुनाव याचिका—

(ए) में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है;

(बी) किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण निर्धारित करेगा जिसका याचिकाकर्ता आरोप लगाता है, जिसमें उन पक्षों के नामों का यथासंभव पूरा विवरण शामिल है जिन पर ऐसा भ्रष्ट आचरण करने का आरोप है और ऐसे प्रत्येक आचरण के किए जाने की तारीख और स्थान; और

(सी) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अभिवचनों के सत्यापन के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा:

[बशर्ते कि जहां याचिकाकर्ता किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाता है, वहां याचिका के साथ ऐसे भ्रष्ट आचरण के आरोप और उसके विवरण के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में एक शपथपत्र भी होगा।]

(2) याचिका की कोई भी अनुसूची या अनुलग्नक भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसी तरह सत्यापित किया जाएगा जैसे याचिका।]

14. धारा 86 के अनुसार, उच्च न्यायालय को ऐसी चुनाव याचिका को खारिज करने का अधिकार है जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है। धारा 87 उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है जो इस प्रकार है:

"87. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया।—

(1) इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक **चुनाव याचिका** का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा, यथासंभव, वादों के विचारण के लिए **दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908** (1908 का 5) के तहत लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:

बशर्ते कि उच्च न्यायालय के पास लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी गवाह या गवाहों की परीक्षा करने से इनकार करने का विवेक होगा यदि उसकी राय है कि ऐसे गवाह या गवाहों का साक्ष्य याचिका के निर्णय के लिए **भौतिक** नहीं है या कि ऐसे गवाह या गवाहों को पेश करने वाला पक्ष तुच्छ आधारों पर या कार्यवाही में देरी करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के प्रावधान, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चुनाव याचिका के विचारण के लिए सभी मामलों में लागू माने जाएंगे।"

15. जिन आधारों पर उच्च न्यायालय निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है, उन्हें धारा 100 में गिनाया गया है जो इस प्रकार है:-

100. चुनाव को शून्य घोषित करने के आधार। - (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन यदि उच्च न्यायालय की राय है-

(ए) —

(बी) —

(सी) —

(डी) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक इसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है-

(i) —

(ii) —

(iii) —

(iv) संविधान या इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के किसी भी प्रावधान की अवहेलना से, तो उच्च न्यायालय निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करेगा।"

16. तत्काल मामले में, उत्तरदाता-चुनाव याचिकाकर्ता ने अपीलकर्ता के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी है कि चुनाव का परिणाम, जहां तक इसका संबंध अपीलकर्ता से था, संविधान के अनुच्छेद 324 की अवहेलना और अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित उक्त नियमों के नियम-4ए की अवहेलना से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 33 नामांकन पत्र के प्रस्तुतीकरण और वैध नामांकन के लिए

आवश्यकताओं से संबंधित है। धारा 36 निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकनों की जाँच-पड़ताल से संबंधित है। इसकी उप-धारा (2) निर्वाचन अधिकारी को, या तो किसी नामांकन पर की गई आपत्तियों पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, उसमें उल्लिखित आधारों पर किसी भी नामांकन को खारिज करने का अधिकार देती है। नामांकन को खारिज करने का एक आधार यह है, जब धारा 33 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता हुई हो। धारा 36 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी किसी भी नामांकन पत्र को किसी ऐसे दोष के आधार पर खारिज नहीं करेगा जो भौतिक प्रकृति का नहीं है।

17. निर्वाचन संचालन नियम, 1961 का भाग-॥ सामान्य प्रावधानों से संबंधित है। नियम-4 और नियम-4 ए जो नामांकन पत्र जमा करने और नामांकन पत्र देते समय दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र के प्रपत्र से संबंधित हैं, इस प्रकार हैं:-

"4. नामांकन पत्र- धारा 33 की उप-धारा (i) के तहत प्रस्तुत प्रत्येक नामांकन पत्र प्रपत्र 2 ए से 2 ई में से किसी एक में पूरा किया जाएगा जो उपयुक्त हो:

बशर्ते कि प्रपत्र 2 ए या प्रपत्र 2 बी में नामांकन पत्र में प्रतीकों के रूप में घोषणा को पूरा करने में विफलता या पूरा करने में दोष को धारा 36 की उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर **भौतिक प्रकृति** का दोष नहीं माना जाएगा।

4 ए. नामांकन पत्र देते समय दाखिल किए जाने वाले शपथपत्र का प्रपत्र- उम्मीदवार या उसका प्रस्थापक, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत

निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र देते समय, उसे प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी या नोटरी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा शपथ लिया हुआ प्रपत्र 26 में एक शपथपत्र भी देगा।"

कानूनी स्थिति:

18. चुनने के अधिकार, चुने जाने के अधिकार और चुनाव को विवादित करने के अधिकार की प्रकृति के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की योजना को 1952 से विभिन्न संवैधानिक पीठों द्वारा समझाया और व्याख्यायित किया गया है। कुछ का हवाला देते हुए *एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र एवं अन्य⁵, जगन नाथ बनाम जसवंत सिंह एवं अन्य में⁶, भीकाजी केशव जोशी एवं अन्य बनाम बृजलाल नंदलाल बियानी एवं अन्य में⁷, मुरारका राधेश्याम राम कुमार बनाम रूप सिंह राठौर एवं अन्य में⁸* आदि।

19. उक्त प्राधिकरणों से जो कुछ भी प्राप्त किया गया है, उसे यह कहकर संक्षेपित किया जा सकता है कि चुनने का अधिकार, यद्यपि यह लोकतंत्र के लिए मौलिक है, न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून अधिकार। यह पूर्णतः एक वैधानिक अधिकार है। इसी प्रकार, चुने जाने का अधिकार और चुनाव को विवादित करने का अधिकार भी वैधानिक अधिकार हैं। चूंकि वे वैधानिक रचनाएं हैं, वे वैधानिक सीमाओं के अधीन हैं। एक चुनाव याचिका सामान्य कानून पर कोई कार्रवाई नहीं है, और न ही समता में। यह एक विशेष क्षेत्राधिकार है जिसका

5 1952 (1) एससीसी 94

6 एआईआर 1954 एससी 210

7 एआईआर 1955 एससी 610

8 एआईआर 1964 एससी 1545

प्रयोग इसे बनाने वाले कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। सामान्य कानून और समता से परिचित अवधारणा चुनाव कानून के लिए अजनबी बनी रहनी चाहिए जब तक कि वैधानिक रूप से सन्निहित न हो। इस प्रकार, एक सदस्य या सदस्यों का चुनाव करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र को बुलाने वाली अधिसूचना जारी होने से लेकर चुनाव से संबंधित विवाद के अंतिम समाधान तक शुरू होने वाली पूरी चुनाव प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा विनियमित होती है। इसलिए उक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को एक पूर्ण और स्व-निहित संहिता अभिनिर्धारित किया गया है जिसके भीतर चुनाव विवाद के संबंध में दावा किए गए किसी भी अधिकार को पाया जाना चाहिए।

20. *भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य*⁹ के मामले में एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण निर्णय में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक प्रश्न उठाते हुए- गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले राष्ट्र में, क्या वोट डालने से पहले, मतदाताओं को संसद या राज्यों के विधान-मंडल के चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों के प्रासंगिक विवरण जानने का अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर विचार किया, और निम्नानुसार देखा:-

"46. उपरोक्त चर्चा से उभरने वाली कानूनी और संवैधानिक स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि:

1. निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार चुनावों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी शक्तियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है और शब्द "चुनाव" का उपयोग

व्यापक अर्थ में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसमें कई चरण होते हैं और कई कदम शामिल होते हैं।

2. शक्ति की परिपूर्ण प्रकृति पर सीमा तब होती है जब संसद या राज्य विधानमंडल ने चुनावों से संबंधित या उसके संबंध में कोई वैध कानून बनाया है, आयोग को उक्त प्रावधानों के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है। ऐसे मामले में जहां कानून मौन है, अनुच्छेद 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के घोषित उद्देश्य के लिए कार्य करने के लिए शक्ति का भंडार है। संविधान ने संविधान के एक प्राणी के रूप में अपने स्वयं के अधिकार में आयोग द्वारा अवशिष्ट शक्ति के प्रयोग की गुंजाइश छोड़ने का ध्यान रखा है, उन अनंत विभिन्न स्थितियों में जो एक बड़े लोकतंत्र में समय-समय पर उभर सकती हैं, क्योंकि अधिनियमित कानूनों या नियमों द्वारा हर आकस्मिकता का अनुमान या पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। आवश्यक निर्देश जारी करके, आयोग उस समय तक शून्यता को भर सकता है जब तक कि विषय पर कानून न हो। कन्हैया लाल उमर मामले [(1985) 4 एस.सी.सी. 628] में न्यायालय ने अनुच्छेद 324(1) में अभिव्यक्ति "अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण" का अर्थ लगाया और अभिनिर्धारित किया कि एक निर्देश का अर्थ किसी विशेष व्यक्ति को जारी किया गया आदेश या एक आज्ञापत्र हो सकता है जिसका कई लोगों को पालन करना पड़ सकता है और यह एक विशिष्ट या सामान्य आदेश हो सकता है और ऐसे वाक्यांश का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए जो निर्वाचन आयोग को ऐसे आदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है।

3.

4. चुनावों की शुद्धता बनाए रखने और विशेष रूप से चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, आयोग उम्मीदवारों से राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च के बारे में पूछ सकता है और चुनाव की प्रक्रिया में इस पारदर्शिता में उस उम्मीदवार की पारदर्शिता शामिल होगी जो चुनाव या पुनः चुनाव चाहता है। लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया की रणनीतिक भूमिका होती है। इस देश के आम आदमी को उस उम्मीदवार का पूरा विवरण जानने का बुनियादी प्राथमिक अधिकार होगा जो संसद में उसका प्रतिनिधित्व करने वाला है जहां उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति को बाध्य करने वाले कानून बनाए जा सकते हैं।"

21. यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि उक्त नियमों में नियम-4 ए और प्रपत्र-26 का अंतःस्थापन भी उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई उक्त टिप्पणियों की परिणति है, जो उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले शपथपत्र के रूप में जानकारी और विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता रखते हैं।

22. इस मामले में उत्तरदाता-चुनाव याचिकाकर्ता ने उक्त नियम-4 ए और प्रपत्र-26 की अवहेलना के आधार पर धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी है। हालांकि, अपीलकर्ता ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 11 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 83(1)(ए) के प्रावधानों की अवहेलना के लिए चुनाव याचिका को प्रारंभ में ही खारिज करने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए थे।

23. ईपी अधिनियम की धारा 83(1)(ए) की आवश्यकता की अवहेलना, अर्थात् - "एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है", के संबंध में इस न्यायालय द्वारा अब तक विकसित और तय किया गया

कानून यह है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII, नियम 11 के साथ पठित धारा 83(1)(ए) की ऐसी अवहेलना चुनाव याचिका को शुरूआत पर ही खारिज करने का कारण बन सकती है। "भौतिक तथ्य" वे तथ्य हैं जिन्हें यदि स्थापित किया जाता है तो याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत मिल जाएगी। जिस परीक्षण का उत्तर दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या न्यायालय चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में सीधा निर्णय दे सकता था यदि निर्वाचित उम्मीदवार याचिका में अभिवचन किए गए तथ्यों के आधार पर चुनाव याचिका का विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ होता। वे ऐसे तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए आधार प्रदान करें और दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में समझे गए अनुसार वाद हेतु का गठन करें। भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक बयान और साथ ही नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक बयान शामिल होगा।

24. हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी (उपरोक्त) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83(1)(ए) से निपटने का अवसर मिला था और न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए चुनाव याचिका को खारिज कर दिया कि चुनाव याचिकाओं में किए गए कोरे और अस्पष्ट प्रकथन दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 की आवश्यकताओं के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83(1)(ए) के अर्थ के भीतर "भौतिक तथ्यों" के अभिवचन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। कंडिका 23 और 24 में निम्नानुसार देखा गया: -

"23. आरपीए, 1951 की धारा 83(1)(ए) यह अनिवार्य करती है कि एक चुनाव याचिका में उन *भौतिक तथ्यों* का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है। इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा, यह अच्छी तरह से तय है कि

बताए जाने वाले आवश्यक भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन्हें लगाए गए आरोपों का समर्थन करने वाली सामग्री के रूप में माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए आधार प्रदान करें और दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 में समझे गए अनुसार वाद हेतु का गठन करें। अभिव्यक्ति "वाद हेतु" को संक्षिप्त रूप से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है प्रत्येक तथ्य जिसे साबित करना वादी के लिए आवश्यक होगा, यदि न्यायालय के निर्णय के लिए उसके अधिकार का समर्थन करने के लिए उसका खंडन किया जाता है। एक भी भौतिक तथ्य का लोप अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाता है और दावे का बयान गलत हो जाता है। पक्ष का कार्य वाद हेतु की पूरी तस्वीर को विस्तार से ऐसी और जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है जिससे विपक्षी उस मामले को समझ सके जिसका उसे सामना करना होगा। (देखें *सामंत एन. बालकृष्ण बनाम जॉर्ज फर्नांडीज* [(1969) 3 एस.सी.सी. 238 : (1969) 3 एस.सी.आर. 603], *जितेंद्र बहादुर सिंह बनाम कृष्ण बिहारी* [(1969) 2 एस.सी.सी. 433]।) केवल मंत्र के जाप की तरह धारा के शब्दों को उद्धृत करना भौतिक तथ्य बताने के बराबर नहीं है। भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक बयान और साथ ही यदि आवश्यक हो तो नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रकथन शामिल होगा। *वी.एस. अच्युतानंदन बनाम पी.जे. फ्रांसिस* [(1999) 3 एस.सी.सी. 737] में इस न्यायालय ने, इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला के अवलोकन पर, यह अभिनिर्धारित किया है कि भौतिक तथ्य ऐसे प्रारंभिक तथ्य हैं जिन्हें वाद हेतु के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए किसी पक्ष द्वारा विचारण में साबित किया जाना चाहिए। "भौतिक तथ्यों" का अभिवचन करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है और चुनाव याचिका दायर करने के लिए

निर्धारित समय-सीमा के बाद ऐसे भौतिक तथ्यों को पेश करने के लिए अभिवचनों में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं है।

24. किसी भी लिखित बयान या इनकार के बावजूद याचिका की जांच करना और यदि यह वाद हेतु का खुलासा नहीं करती है तो याचिका को अस्वीकार करना न्यायालय का कर्तव्य है। यह आधार पर कि यह वाद हेतु का खुलासा नहीं करता है, एक अभियोग को अस्वीकार करने के लिए न्यायालय को सक्षम करने हेतु, उसे अभियोग को देखना चाहिए और कुछ नहीं। न्यायालयों ने हमेशा अस्पष्ट अभिवचनों पर नाराजगी जताई है जो कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए व्यापक गुंजाइश छोड़ते हैं। साक्ष्य की कोई भी मात्रा अभिवचनों में बुनियादी दोष को ठीक नहीं कर सकती है।"

25. *महादेवराव सुकाजी शिवनकर बनाम रामरतन बापू एवं अन्य*¹⁰ के मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को फिर से उन मुद्दों से निपटने का अवसर मिला कि क्या "भौतिक तथ्य" का गठन करेगा और चुनाव याचिका में "भौतिक तथ्यों" को न बताने के क्या परिणाम होंगे, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83(1)(ए) में परिकल्पित है, और न्यायालय ने निम्नानुसार देखा:

"6. अब, यह निस्संदेह सच है कि सभी भौतिक तथ्यों को चुनाव याचिका में निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि अभियोग या याचिका में भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो इसे केवल उस आधार पर खारिज किया जा सकता है क्योंकि मामला संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (ए) के अंतर्गत आएगा। हालांकि, सवाल यह है कि क्या

10 2004 (7) एससीसी 181

याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य निर्धारित किए थे। अभिव्यक्ति "भौतिक तथ्य" को न तो अधिनियम में और न ही संहिता में परिभाषित किया गया है। यह कहा जा सकता है कि भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन पर कोई पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए अवलंबन करता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक तथ्य वे तथ्य हैं जिन पर वादी का वाद हेतु या प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है। किन् विवरणों को भौतिक तथ्य कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह बिल्कुल आवश्यक है कि सभी बुनियादी और प्राथमिक तथ्य जिन्हें वाद हेतु या बचाव के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पक्ष द्वारा विचारण में साबित किया जाना चाहिए, वे भौतिक तथ्य हैं और उन्हें पक्ष के अभिवचन में बताया जाना चाहिए।

7. लेकिन, यह भी समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि "भौतिक तथ्यों" और "विवरणों" के बीच अंतर है। भौतिक तथ्य प्राथमिक या बुनियादी तथ्य हैं जिनका अभिवचन याचिकाकर्ता द्वारा अपने द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में या तो अपने वाद हेतु या बचाव को साबित करने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, विवरण, पक्ष द्वारा अभिवचन किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण हैं। वे पहले से खींची गई तस्वीर की बुनियादी रूपरेखा को अंतिम स्पर्श देकर भौतिक तथ्यों को विस्तृत, परिष्कृत और संवारते हैं ताकि इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सके। विवरण निष्पक्ष विचारण का संचालन सुनिश्चित करते हैं और विपक्षी को आश्चर्यचकित नहीं करते हैं।"

26. *अनिल वासुदेव सालगांवकर बनाम नरेश कुशली शिगांवकर*¹¹ में, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर कई पहले के निर्णयों पर चर्चा की है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 के साथ पठित दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि यह वाद हेतु प्रस्तुत नहीं करता है तो चुनाव याचिका को कब संक्षेप में खारिज किया जा सकता है।

"50. स्थिति अच्छी तरह से तय है कि एक चुनाव याचिका को संक्षेप में खारिज किया जा सकता है यदि यह दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए वाद हेतु प्रस्तुत नहीं करती है। संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त आदेश पारित किए जा सकते हैं यदि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों को शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 83 द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है।

51. इस न्यायालय ने *सामंत एन. बालकृष्ण मामले* [(1969) 3 एस.सी.सी. 238] में खुद को अनिश्चित शब्दों में व्यक्त किया है कि एक भी भौतिक तथ्य का लोप अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाएगा और यह कि भ्रष्ट आचरण से संबंधित भौतिक तथ्यों के बिना एक चुनाव याचिका बिल्कुल भी चुनाव याचिका नहीं है। *उधव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया* [(1977) 1 एस.सी.सी. 511] में कानून को प्रतिपादित किया गया है कि सभी प्राथमिक तथ्य जिन्हें किसी पक्ष द्वारा वाद हेतु या उसके बचाव को स्थापित करने के लिए साबित किया जाना चाहिए, भौतिक तथ्य हैं। भ्रष्ट आचरण के आरोप के संदर्भ में इसका मतलब यह होगा कि बुनियादी तथ्य जो याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए विशेष भ्रष्ट आचरण के घटकों का गठन करते हैं, आरोप पर सफल होने के लिए निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। क्या एक चुनाव याचिका में कोई विशेष तथ्य भौतिक है या नहीं और इस तरह

अभिवचन किया जाना आवश्यक है, यह लगाए गए आरोप की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वे सभी तथ्य जो याचिका को पूर्ण वाद हेतु के साथ तैयार करने के लिए आवश्यक हैं, उनका अभिवचन किया जाना चाहिए और एक भी भौतिक तथ्य का अभिवचन करने में विफलता धारा 83(1)(ए) के जनादेश की अवज्ञा के बराबर होगी। इसलिए, एक चुनाव याचिका को खारिज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए यदि वह किसी ऐसे दोष से ग्रस्त है। इसलिए चुनौती का पहला आधार विफल होना चाहिए।

52. *वी. नारायणस्वामी बनाम सी.पी. थिरुनावुक्कारासु* [(2000) 2 एस.सी.सी. 294] में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को दोहराया कि यदि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का अभाव है तो उसे खारिज किया जा सकता है। *एल.आर. शिवरामगौडा बनाम टी.एम. चंद्रशेखर* [(1999) 1 एस.सी.सी. 666] में इस न्यायालय ने फिर से अधिनियम की धारा 123 के दायरे में आने वाले भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाने वाली चुनाव याचिका में अभिवचनों के महत्व पर विचार किया और निम्नानुसार देखा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 677, कंडिका 11)

"11. इस न्यायालय ने बार-बार एक चुनाव याचिका में अभिवचनों के महत्व पर जोर दिया है और 'भौतिक तथ्यों' और 'भौतिक विवरणों' के बीच अंतर बताया है। जबकि भौतिक तथ्यों का अभिवचन करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है और चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के बाद ऐसे भौतिक तथ्यों को पेश करने के लिए अभिवचन में किसी भी संशोधन की

अनुमति नहीं दी जा सकती है, भौतिक विवरणों की अनुपस्थिति को बाद के चरण में एक उपयुक्त संशोधन द्वारा ठीक किया जा सकता है।"

53. *उधव सिंह मामले* [(1977) 1 एस.सी.सी. 511] में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 522-23, कंडिका 41)

"41. दीवानी प्रक्रिया संहिता की तरह, यह धारा भी 'भौतिक तथ्यों' और 'भौतिक विवरणों' के बीच एक अंतर की परिकल्पना करती है। उप-धारा (1) का खंड (ए) आदेश 6 नियम 2 से मेल खाता है, जबकि खंड (बी) संहिता के आदेश 6 नियम 4 और 6 के अनुरूप है। 'भौतिक तथ्यों' और 'भौतिक विवरणों' के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिवचन में ऐसे तथ्यों या विवरणों की कमी से अलग-अलग परिणाम निकल सकते हैं। एक भी *भौतिक तथ्य* का अभिवचन करने में विफलता अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाती है और ऐसे आरोप के अपूर्ण आरोपों को दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 के तहत हटाया जा सकता है। यदि याचिका पूरी तरह से उन आरोपों पर आधारित है जो *भौतिक तथ्यों* की कमी से ग्रस्त हैं, तो याचिका वाद हेतु के अभाव में संक्षेप में खारिज किए जाने योग्य है। *भौतिक विवरणों* की कमी से ग्रस्त याचिका के मामले में, न्यायालय के पास परिसीमा की समाप्ति के बाद भी याचिकाकर्ता को आवश्यक विवरण प्रदान करने की अनुमति देने का विवेक है।"

54. *एच.डी. रेवन्ना मामले* [(1999) 2 एस.सी.सी. 217] में अपील उस उम्मीदवार द्वारा दायर की गई थी जो चुनाव में सफल हुआ था और जिसका चुनाव याचिका को आरम्भ

में ही खारिज करने का आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इस न्यायालय ने देखा कि इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि धारा 83 के प्रावधानों की अवहेलना से याचिका खारिज हो सकती है यदि मामला दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 16 और आदेश 7 नियम 11 के दायरे में आता है। *हरमोहिंदर सिंह प्रधान बनाम रंजीत सिंह तलवंडी* [(2005) 5 एस.सी.सी. 46] में इस न्यायालय ने इस प्रकार देखा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 51, कंडिका 14)

"14. 'उसके धर्म' के आधार पर वोट देने या मतदान से विरत रहने की अपील का गठन करने वाले तथ्यों का आवश्यक प्रकथन, अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अर्थ के भीतर भौतिक तथ्य होगा। यदि ऐसे भौतिक तथ्य गायब हैं, तो उन्हें बाद में, चुनाव याचिका दाखिल करने की परिसीमा अवधि की समाप्ति के बाद आपूर्ति नहीं की जा सकती है और दलील अपूर्ण होने के कारण, दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 6 नियम 16 के तहत खारिज करने का निर्देश दिया जा सकता है और यदि ऐसी दलील चुनाव याचिका दाखिल करने का एकमात्र आधार हो, तो याचिका को ही संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (ए) के तहत वाद हेतु का खुलासा न करने के रूप में खारिज किया जा सकता है।"

55. *हरकीरत सिंह बनाम अमरिंदर सिंह* [(2005) 13 एस.सी.सी. 511] में इस न्यायालय ने फिर से "भौतिक तथ्यों" और "भौतिक विवरणों" के बीच के अंतर को दोहराया और निम्नानुसार देखा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 527, कंडिका 51-52)

"51. हालांकि, 'भौतिक तथ्यों' और 'विवरणों' के बीच के अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 'भौतिक तथ्य' प्राथमिक या बुनियादी तथ्य हैं जिनका

अभिवचन वादी या प्रतिवादी द्वारा अपने द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में या तो अपने वाद हेतु या बचाव को साबित करने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, 'विवरण', पक्ष द्वारा अभिवचन किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण हैं। वे पहले से खींची गई तस्वीर की बुनियादी रूपरेखा को विशिष्ट स्पर्श देकर भौतिक तथ्यों को विस्तृत, परिष्कृत और संवारते हैं ताकि इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सके। इस प्रकार 'विवरण' निष्पक्ष विचारण का संचालन सुनिश्चित करते हैं और विपक्षी को आश्चर्यचकित नहीं करते हैं।

52. सभी 'भौतिक तथ्यों' का अभिवचन पक्ष द्वारा उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में किया जाना चाहिए। चूंकि उद्देश्य और प्रयोजन विपक्षी को उस मामले को जानने में सक्षम बनाना है जिसका उसे सामना करना है, अभिवचन के अभाव में, किसी पक्ष को साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, एक भी भौतिक तथ्य को बताने में विफलता, वाद या याचिका को खारिज करने का कारण बनेगी। दूसरी ओर, विवरण, मामले के विवरण हैं जो साक्ष्य की प्रकृति में हैं जिसका नेतृत्व एक पक्ष विचारण के समय करेगा।"

56. *सुदर्शा अवस्थी बनाम शिव पाल सिंह* [(2008) 7 एस.सी.सी. 604] में इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 612, कंडिका 20)

"20. चुनाव याचिका एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में या काल्पनिक तरीके से नहीं लिया जा सकता है और न ही यह किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इसका उपयोग तंग करने वाले उद्देश्य के लिए करता है।"

57. यह तय कानूनी स्थिति है कि सभी "भौतिक तथ्यों" का अभिवचन पक्ष द्वारा परिसीमा की अवधि के भीतर उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में किया जाना चाहिए। चूंकि उद्देश्य और प्रयोजन विपक्षी को उस मामले को जानने में सक्षम बनाना है जिसका उसे सामना करना है, अभिवचन के अभाव में, किसी पक्ष को साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एक भी भौतिक तथ्य बताने में विफलता चुनाव याचिका को खारिज करने का कारण बनेगी। चुनाव याचिका में उन "भौतिक तथ्यों" का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है।

58. "भौतिक तथ्यों" की कोई परिभाषा न तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में है और न ही दीवानी प्रक्रिया संहिता में। निर्णयों की एक श्रृंखला में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि पूर्ण वाद हेतु तैयार करने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों को "भौतिक तथ्य" कहा जाना चाहिए। सभी बुनियादी और प्राथमिक तथ्य जो वाद हेतु या बचाव के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए किसी पक्ष द्वारा साबित किए जाने चाहिए, वे भौतिक तथ्य हैं। दूसरे शब्दों में "भौतिक तथ्य" का अर्थ तथ्यों का पूरा पुलिंदा है जो एक पूर्ण वाद हेतु का गठन करेगा। इस न्यायालय ने *हरकीरत सिंह मामले* [(2005) 13 एस.सी.सी. 511] में "भौतिक तथ्यों" के विभिन्न अर्थ देने का प्रयास किया। उक्त निर्णय की प्रासंगिक कंडिका 48 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 526-27)

"48. अभिव्यक्ति 'भौतिक तथ्य' को न तो अधिनियम में और न ही संहिता में परिभाषित किया गया है। शब्दकोश के अर्थ के अनुसार, 'भौतिक' का अर्थ है 'मौलिक', 'महत्वपूर्ण', 'बुनियादी', 'प्रमुख', 'केंद्रीय', 'निर्णायक', 'आवश्यक', 'धुरी', 'अपरिहार्य', 'प्रारंभिक' या 'प्राथमिक'। [*बर्टन का लीगल थिसॉरस* (तीसरा

संस्करण), पृष्ठ 349।] इसलिए, वाक्यांश 'भौतिक तथ्य' को वे तथ्य कहा जा सकता है जिन पर कोई पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए अवलंबन करता है। दूसरे शब्दों में, 'भौतिक तथ्य' वे तथ्य हैं जिन पर वादी का वाद हेतु या प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है। किन विवरणों को 'भौतिक तथ्य' कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह बिल्कुल आवश्यक है कि सभी बुनियादी और प्राथमिक तथ्य जिन्हें वाद हेतु या बचाव के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पक्ष द्वारा विचारण में साबित किया जाना चाहिए, वे भौतिक तथ्य हैं और उन्हें पक्ष द्वारा अभिवचन में बताया जाना चाहिए।"

27. *राम सुख बनाम दिनेश अग्रवाल* (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत दायर चुनाव याचिका की पोषणीयता की जांच करते हुए, पहले के निर्णयों पर विस्तार से विचार किया और देखा कि चुनाव याचिकाकर्ता के लिए यह विशेष रूप से सिद्ध करना आवश्यक था कि निर्वाचन अधिकारी की ओर से चूक के कारण निर्वाचित उम्मीदवार के संबंध में चुनाव का परिणाम किस प्रकार भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। उक्त मामले में न्यायालय ने यह पाया कि चुनाव याचिका में ऐसे प्रकथन नदारद थे, उच्च न्यायालय/चुनाव न्यायाधिकरण के उस निर्णय को सही ठहराया जिसमें चुनाव याचिका को शुरुआत पर ही खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने कंडिका 14 से 21 में निम्नानुसार देखा:-

"14. अधिनियम की धारा 81, 83 और 86 के संदर्भ में भौतिक तथ्यों के बयान और ऐसे खुलासे की कमी के परिणामों के रूप में चुनाव याचिका में आवश्यकता इस

न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष *सामंत एन. बालकृष्ण बनाम जॉर्ज फर्नांडीज* [(1969) 3 एस.सी.सी. 238] में विचार के लिए आई। तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए, एम. हिदायतुल्ला, मुख्य न्यायाधीश, ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया कि:

(i) अधिनियम की धारा 83 अनिवार्य है और पहले भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त विवरण और फिर यथासंभव पूर्ण विवरण की आवश्यकता होती है;

(ii) एक भी भौतिक तथ्य को छोड़ देने से कार्रवाई का एक अधूरा कारण बन जाता है और दावे का बयान गलत हो जाता है।

(iii) विवरणों का कार्य वाद हेतु की पूरी तस्वीर पेश करना और विपक्षी को उस मामले को समझाना है जिसका उसे सामना करना होगा;

(iv) भौतिक तथ्य और विवरण अलग-अलग मामले हैं—भौतिक तथ्य तथ्यों के बयानों का उल्लेख करेंगे और विवरण तारीख, समय और स्थान के साथ व्यक्तियों के नाम निर्धारित करेंगे; और

(v) भौतिक तथ्यों को बताते समय केवल धारा के शब्दों को उद्धृत करना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि तब भौतिक तथ्यों की प्रभावकारिता खो जाएगी।

15. इस मोड़ पर, वाक्यांश "भौतिक तथ्यों" के वास्तविक उद्देश्य और तात्पर्य की सराहना करने के लिए, विशेष रूप से चुनाव कानून के संदर्भ में, धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में दिखाई देने वाले वाक्यांश "भौतिक तथ्यों" और खंड (बी) में दिखाई देने वाले "विवरणों" के बीच के अंतर को नोटिस करना उचित होगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, "भौतिक तथ्य" प्राथमिक या बुनियादी तथ्य हैं जिनका अभिवचन याचिकाकर्ता द्वारा अपने वाद हेतु को साबित करने के लिए और प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव को साबित करने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, "विवरण", पक्षों द्वारा अभिवचन किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण हैं। वे पहले से खींची गई तस्वीर की बुनियादी रूपरेखा को विशिष्ट स्पर्श देकर भौतिक तथ्यों को विस्तृत, परिष्कृत और संवारते हैं ताकि इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट और अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सके। "भौतिक तथ्यों" के विपरीत, जो वह बुनियादी नींव प्रदान करते हैं जिस पर चुनाव याचिका की पूरी इमारत बनी होती है, "विवरणों" को यह सुनिश्चित करने के लिए बताया जाना चाहिए कि विपक्षी आश्चर्यचकित न हो।

16. "भौतिक तथ्यों" और "विवरणों" के बीच अंतर और चुनाव याचिका में उनकी आवश्यकता को इस न्यायालय ने *वीरेंद्र नाथ गौतम बनाम सतपाल सिंह* [(2007) 3 एस.सी.सी. 617] में संक्षिप्त रूप से सामने लाया था, जिसमें सी.के. ठक्कर, न्यायमूर्ति ने इस प्रकार कहा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 631-32, कंडिका 50)

"50. सिद्ध किए जाने वाले तथ्य(फैक्टा प्रोबेंडा) (तथ्य जिन्हें साबित किया जाना आवश्यक है यानी भौतिक तथ्य) और तथ्य साबित कर रहे हैं(फैक्टा प्रोबेंसिया) (वे तथ्य जिनके माध्यम से उन्हें साबित किया जाता है यानी विवरण या साक्ष्य) के बीच अंतर है।

यह तय कानून है कि अभिवचनों में केवल सिद्ध किए जाने वाले तथ्य(फैक्टा प्रोबेंडा) होना चाहिए और तथ्य साबित कर रहे हैं(फैक्टा प्रोबेंसिया) नहीं। वे भौतिक तथ्य जिन पर पक्ष अपने दावे के लिए अवलंबन करता है, सिद्ध किए जाने वाले तथ्य(फैक्टा प्रोबेंडा) कहलाते हैं और उन्हें अभिवचनों में बताया जाना चाहिए। लेकिन वे तथ्य या तथ्य जिनके माध्यम से सिद्ध किए जाने वाले तथ्य(फैक्टा प्रोबेंडा) (भौतिक तथ्य) साबित होते हैं और जो तथ्य साबित कर रहे हैं(फैक्टा प्रोबेंसिया) (विवरण या साक्ष्य) की प्रकृति में हैं, उन्हें अभिवचनों में निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। वे मुद्दे में तथ्य नहीं हैं, बल्कि मुद्दे में तथ्य को स्थापित करने के लिए मुकदमे में केवल प्रासंगिक तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता है।"

17. अब, पूर्वोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में परस्पर विरोधी दलीलों की जांच करने से पहले, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की एक और दलील से निपटना उपयोगी होगा कि उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका को शुरुआत पर ही अस्वीकार करने के लिए संहिता के आदेश 6 नियम 16 या आदेश 7 नियम 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। तर्क दोहरे हैं अर्थात:

(i) कि भले ही चुनाव याचिका अंततः खारिज किए जाने योग्य थी, इसे चुनाव याचिकाकर्ता को याचिका में अपने आरोप के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद ही खारिज किया जाना चाहिए था, और

(ii) चूंकि धारा 83 अधिनियम की धारा 86 में जगह नहीं पाती है, इसलिए शुरूआत पर याचिका को खारिज करना धारा 86 की उप-धारा (1) में एक अतिरिक्त आधार को पढ़ने के बराबर होगा।

हमारी राय में, दोनों दलीलें भ्रामक और अस्थिर हैं।

18. निस्संदेह, अधिनियम की धारा 87 के आधार पर, संहिता के प्रावधान चुनाव याचिका के विचारण पर लागू होते हैं और, इसलिए, अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी न होने पर, चुनाव याचिका का विचारण करने वाला न्यायालय संहिता के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जिसमें संहिता का आदेश 6 नियम 16 और आदेश 7 नियम 11 शामिल हैं। दोनों प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्थहीन मुकदमेबाजी, जो अन्यथा निष्फल साबित होने के लिए बाध्य है, को न्यायालयों के न्यायिक समय पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि सामान्य दीवानी मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों में ऐसा है, तो इसे चुनाव मामलों में अधिक सख्ती के साथ लागू होना चाहिए जहां चुनाव याचिका का लंबित होना जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधित करने की संभावना रखता है जिसके लिए मतदाताओं ने उसमें विश्वास जताया है। इसलिए, यह दलील विफल होनी चाहिए।

19. तर्क के दूसरे पहलू पर आते हुए अर्थात् अधिनियम की धारा 86 में धारा 83 की अनुपस्थिति, जो विशेष रूप से एक चुनाव याचिका को खारिज करने का प्रावधान करती है जो अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है, हमारे विचार में, यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं है। इसी तरह की दलील को इस न्यायालय की तीन-

न्यायाधीशों की पीठ ने *हरद्वारी लाल बनाम कंवल सिंह* [(1972) 1 एस.सी.सी. 214] में नकारा था, जिसमें पीठ के लिए बोलते हुए, ए.एन. रे, न्यायमूर्ति (जैसे कि हिज लॉर्डशिप तब थे) ने कहा: (एस.सी.सी. पृष्ठ 221, कंडिका 23)

"23. उत्तरदाता की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भौतिक तथ्यों की कमी के कारण चुनाव याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिनियम की धारा 86 ने उच्च न्यायालय को उस चुनाव याचिका को खारिज करने की शक्ति प्रदान की जो अधिनियम की धारा 81, या धारा 82 या धारा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती थी। इस बात पर जोर दिया गया कि धारा 83 को धारा 86 में जगह नहीं मिली। अधिनियम की धारा 87 के तहत प्रत्येक चुनाव याचिका का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा यथासंभव दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत वादों के विचारण के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। एक मुकदमा जो कार्रवाई का कारण प्रस्तुत नहीं करता है उसे खारिज किया जा सकता है।"

20. इस मुद्दे को फिर से इस न्यायालय द्वारा *अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी* [1986 पूरक एस.सी.सी. 315] में निपटाया गया था। *सामंत एन. बालकृष्ण* [(1969) 3 एस.सी.सी. 238] और *उधव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया* [(1977) 1 एस.सी.सी. 511] में इस न्यायालय की पिछली घोषणाओं का उल्लेख करते हुए जिसमें यह देखा गया था कि एक भी भौतिक तथ्य का लोप अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाएगा और यह कि भौतिक तथ्यों के बिना एक चुनाव याचिका बिल्कुल भी चुनाव याचिका नहीं है, *अजहर हुसैन* मामले [1986 पूरक एस.सी.सी. 315] में पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि वे सभी तथ्य जो याचिका को पूर्ण वाद हेतु के साथ तैयार करने के लिए आवश्यक हैं, उनका

अभिवचन किया जाना चाहिए और एक भी भौतिक तथ्य का लोप अधिनियम की धारा 83(1)(ए) के जनादेश की अवज्ञा के बराबर होगा और एक चुनाव याचिका को खारिज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए यदि वह किसी ऐसे दोष से ग्रस्त है।

21. अब हम यह जांचने के लिए हाथ में मौजूद तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि क्या चुनाव याचिका भौतिक तथ्यों के प्रकटीकरण न करने के दोष से ग्रस्त थी जैसा कि अधिनियम की धारा 83(1)(ए) में निर्धारित है। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि चुनाव याचिकाकर्ता का मामला धारा 100(1)(डी)(iv) के कथित उल्लंघन तक ही सीमित है। तैयार संदर्भ के लिए, उक्त प्रावधान नीचे निकाला गया है:

"100. चुनाव को शून्य घोषित करने के आधार।—

(1) उपधारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए

(2) यदि उच्च न्यायालय की राय हो—

(डी) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक इसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है—

(iv) संविधान या इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के किसी भी प्रावधान की अवहेलना से, उच्च न्यायालय निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करेगा।"

यह स्पष्ट है कि उक्त प्रावधान के तहत चुनाव को शून्य घोषित करवाने के लिए, चुनाव याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना होगा कि संविधान या इस अधिनियम या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों की अवहेलना के कारण, चुनाव का परिणाम, जहां तक इसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था।"

28. पूर्वोक्त मामलों में प्रतिपादित कानूनी स्थिति को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:-

- i. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83(1)(ए) यह अनिवार्य करती है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है। यदि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं, तो इसे केवल उस आधार पर खारिज किया जा सकता है, क्योंकि यह मामला संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (ए) के अंतर्गत आएगा।
- ii. भौतिक तथ्य ऐसे तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों के लिए आधार प्रदान करें और वाद हेतु का गठन करें, अर्थात् प्रत्येक तथ्य जिसे साबित

करना वादी/याचिकाकर्ता के लिए आवश्यक होगा, यदि न्यायालय के निर्णय के लिए उसके अधिकार का समर्थन करने के लिए उसका खंडन किया जाता है। एक भी भौतिक तथ्य का लोप अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाएगा और अभियोग का कथन खराब हो जाएगा।

- iii. भौतिक तथ्यों का अर्थ है तथ्यों का पूरा पुलिंदा जो एक पूर्ण वाद हेतु का गठन करेगा। भौतिक तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक बयान और साथ ही यदि आवश्यक हो तो नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक प्रकथन शामिल होगा।
- iv. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत चुनाव को शून्य घोषित करवाने के लिए, चुनाव याचिकाकर्ता को यह सिद्ध करना होगा कि संविधान या अधिनियम के प्रावधानों या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश की अवहेलना के कारण, चुनाव का परिणाम, जहां तक इसका संबंध निर्वाचित उम्मीदवार से है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था।
- v. चुनाव याचिका एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में या काल्पनिक तरीके से नहीं लिया जा सकता है और न ही यह किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो इसका उपयोग तंग करने वाले उद्देश्य के लिए करता है।
- vi. एक चुनाव याचिका को अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाने वाले एक भी भौतिक तथ्य के लोप पर, या वाद हेतु स्थापित करने के लिए जिन भौतिक तथ्यों पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है उनका संक्षिप्त विवरण शामिल करने में लोप पर,

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ पठित दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII के नियम 11 के खंड (ए) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संक्षेप में खारिज किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

29. पूर्वोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में, आइए देखें कि क्या उत्तरदाता/चुनाव याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में "भौतिक तथ्य" बताते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83(1)(ए) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया था, जो वाद हेतु और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) में परिकल्पित आधार का गठन करते हैं, ताकि अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित किया जा सके। उत्तरदाता-चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए विवाद की जड़ यह है कि भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों के आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति के संबंध में प्रपत्र 26 निर्धारित करते हुए जानकारी मांगी थी और इसमें याचिकाकर्ता ने जानकारी प्रदान की थी कि उसका पति विदेश में सलाहकार के रूप में काम कर रहा था और वेतन कमा रहा था, जिसका उल्लेख प्रपत्र 26 के भाग ए के तहत क्रमशः कॉलम नंबर 8, क्रम सं. 9(बी) और 9 ए(बी) के सामने किया गया था। इसके अलावा, उसने अपने पति के आयकर बकाया के संबंध में प्रश्न के लिए "नहीं" का उल्लेख किया था, (तमिल भाषा में "एथुमिलाई" के रूप में उल्लेखित)। उसने आगे कहा था कि उसके पति के पास सिंगापुर में बैंक खाते हैं जिनमें डॉलर जमा हैं, जिसका उल्लेख प्रपत्र 26 के भाग ए के कॉलम नंबर 7 के क्रम सं. (ii) के सामने किया गया है, लेकिन वह विदेश में अपने पति के आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति का

खुलासा करने में विफल रही थी। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये भौतिक तथ्य जो पहले से ही चुनाव याचिका में बताए जा चुके हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत चुनाव याचिका दायर करने के लिए वाद हेतु का गठन करने के लिए पर्याप्त थे।

30. यह ध्यान दिया जा सकता है कि उत्तरदाता-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अपनी चुनाव याचिका की कंडिका 5 से 9 में लगाए गए सटीक आरोपों को पूर्व में यहाँ पुनरुत्पादित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चुनाव याचिकाकर्ता यानी उत्तरदाता ने यह भौतिक तथ्य बताए बिना बहुत ही कोरे और अस्पष्ट आरोप लगाए हैं कि भारत के संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान की अवहेलना कैसे हुई थी। यदि चुनाव याचिका में किए गए कथनों को अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्रपत्र संख्या 26 में दी गई जानकारी के साथ तुलना करके पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट रूप से उभरता है कि अपीलकर्ता के पति के स्थायी खाता संख्या के बारे में मांगी गई जानकारी के सामने, यह कहा गया है कि "कोई पैन नंबर नहीं", "पति के अरविंदन विदेशी नागरिकता"। "वित्तीय वर्ष जिसके लिए पिछला आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है" के संबंध में मांगी गई जानकारी के सामने, अपीलकर्ता द्वारा अपने पति के बारे में दी गई जानकारी "लागू नहीं" है। अपीलकर्ता ने अपने स्थायी खाता संख्या और आयकर रिटर्न दाखिल करने की स्थिति आदि और जहां लागू हो, अपने पति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करके प्रपत्र संख्या 26 के सभी कॉलम भरे हैं। यदि उत्तरदाता-चुनाव याचिकाकर्ता के अनुसार, अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार ने अपने पति के स्थायी खाता संख्या और विदेशी देश में अपने पति द्वारा आयकर का भुगतान न करने के बारे में भी छिपाया था, तो चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव याचिका में यह बताना अनिवार्य था कि भारत में निर्वाचित उम्मीदवार के पति का स्थायी खाता संख्या क्या था

जिसे उसने छिपाया था और उक्त प्रपत्र संख्या 26 में उसके पति के बारे में प्रस्तुत अन्य विवरण कैसे अधूरे या झूठे थे।

31. बिना किसी आधार के केवल कोरे और अस्पष्ट आरोप चुनाव याचिका में भौतिक तथ्य बताने की आवश्यकता के पर्याप्त अनुपालन नहीं होंगे। जैसा कि अच्छी तरह से तय है, न केवल तथ्यों का सकारात्मक बयान, यहां तक कि नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक बयान भी बताया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह वाद हेतु का गठन करने वाला एक भौतिक तथ्य होगा। भौतिक तथ्य जो प्राथमिक और बुनियादी तथ्य हैं, उनका अभिवचन चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में अपने वाद हेतु को दिखाने के लिए किया जाना चाहिए और एक भी भौतिक तथ्य का लोप अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाएगा, जो निर्वाचित उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83(1)(ए) के साथ पठित दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11(ए) के तहत चुनाव याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करने का हकदार बनाता है।

32. यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उक्त नियमों के नियम 4 ए के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 33 के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रपत्र 26 में एक शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। निर्वाचन अधिकारी को किसी भी नामांकन पर की गई आपत्तियों पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, धारा 36(2) में उल्लिखित आधारों पर किसी भी नामांकन को खारिज करने का अधिकार है, जिसमें यह आधार भी शामिल है कि अधिनियम की धारा 33 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता हुई है। हालांकि, नामांकन पत्र और अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र 26 में शपथपत्र की जाँच-पड़ताल के समय, न तो कोई आपत्ति उठाई गई थी, और न ही निर्वाचन अधिकारी ने धारा 33 या नियमों

के नियम 4 ए की कोई चूक या अवहेलना पाई थी। यह मानते हुए कि चुनाव याचिकाकर्ता के पास अपीलकर्ता-निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भरे गए प्रपत्र संख्या 26 को देखने का अवसर नहीं था, जब उसने उसे निर्वाचन अधिकारी को सौंपा था, और यह मानते हुए कि निर्वाचन अधिकारी ने अपीलकर्ता के नामांकन पत्र की ठीक से जांच नहीं की थी, और यह मानते हुए कि चुनाव याचिकाकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत चुनाव याचिका दायर करके उस पर सवाल उठाने का अधिकार था, तब भी याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत वाद हेतु का गठन करने वाले कोई भौतिक तथ्य नहीं बताए गए हैं। उक्त अधिनियम की धारा 100(1)(डी)(iv) के तहत चुनाव याचिका दायर करने के लिए वाद हेतु का गठन करने वाले भौतिक तथ्यों के अभाव में, चुनाव याचिका को आदेश VII नियम 11(ए) दीवानी प्रक्रिया संहिता पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13(1)(ए) [नोट: यह 83(1)(ए) होना चाहिए] के तहत खारिज किया जाना आवश्यक है।

33. जैसा कि पहले विस्तार से चर्चा की गई है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83(1)(ए) यह अनिवार्य करती है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अवलंबन करता है, और जो तथ्य वाद हेतु का गठन करते हैं। ऐसे तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक बयान और साथ ही नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक कथन शामिल होगा। एक भी तथ्य का लोप अपूर्ण वाद हेतु की ओर ले जाएगा। जहां तक वर्तमान याचिका का संबंध है, ऐसा कोई प्रकथन नहीं किया गया है कि संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेश के प्रावधानों की अवहेलना कैसे हुई और ऐसी अवहेलना ने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से कैसे प्रभावित किया, जिससे चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा

100(1)(डी)(iv) के तहत आधार आकर्षित हो। ऐसे महत्वपूर्ण और बुनियादी तथ्यों को बताने में लोप ने याचिका को आदेश VII, नियम 11(ए) दीवानी प्रक्रिया संहिता पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83(i)(ए) के तहत खारिज किए जाने योग्य बना दिया है।

34. मामले के उस दृष्टिकोण में, उत्तरदाता-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका संख्या 3/2019 खारिज किए जाने योग्य है, और तदनुसार खारिज की जाती है।

35. उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। तदनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

दिव्या पांडे

अपीलें स्वीकार

(सहायता : भव्यता कपूर और रूपंशी विरांग, एलसीआरए)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।